रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3572] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 31, 2019/कार्तिक 9, 1941
No. 3572] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 2019/ KARTIKA 9, 1941

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3964**(अ)**.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ बावनवां संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-

(क) प्रथम अनुसूची में, "17. गृह मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "(v) जम्मू तथा कश्मीर विभाग" उप-शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात:-

"(v) जम्मू, कश्मीर और लद्दाख विभाग";

(ख) द्वितीय अनुसूची में, "गृह मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, " ङ. जम्मू तथा कश्मीर विभाग" उप-शीर्षक और उसके अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

"**ङ. जम्मू, कश्मीर और लद्दाख विभाग**

क. सामान्य:

1. संविधान के भाग VIII में अंतर्विष्ट उपबंधों के निबंधनों में संघ सरकार के कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी मामले, जहां तक वे, यथास्थिति, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को लागू होते हैं, सिवाय, ऐसे सभी मामलों के, जिनको इन नियमों के अधीन भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विनिर्दिष्ट रूप से सौंपा गया है।

2. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के उपबंधों के निबंधनों में संघ राज्यक्षेत्र के कार्य क्षेत्र में आने वाले दोनों संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित सभी मामले सिवाय, ऐसे सभी मामलों के, जिनको इन नियमों के अधीन भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विनिर्दिष्ट रूप से सौंपा गया है।

3. यथास्थिति, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित सभी मामले, जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के भीतर आतंकवाद से मुकाबला और भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा की निगरानी और प्रबंधन के संबंध में रक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय सम्मिलित है। किंतु इसके अंतर्गत वे मामले नहीं हैं, जिनका संबंध विदेश मंत्रालय से है।

4. दोनों संघ राज्यक्षेत्रों में सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 (1990 का 21) का प्रशासन।

5. संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन विभिन्न अधिनियमनों के अधीन, यथास्थिति, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की शक्तियों को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र अथवा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या उप-राज्यपाल को प्रत्यायोजित करना।

ख. लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए विशिष्ट उपबंध:

6. संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बनाना।

7. राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित सभी मामले, जहां तक कि ऐसा कोई मामला, उक्त संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित है, सिवाय, ऐसे सभी मामलों के, जिनको इन नियमों के अधीन भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विनिर्दिष्ट रूप से सौंपा गया है।

8. लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में लोक सेवाओं से संबंधित सामान्य प्रश्न और सेवा संबंधी मामले, जहां तक वे राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

ग. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के लिए विशिष्ट उपबंध:

9. उक्त संघ राज्यक्षेत्र में लोक सेवाओं से संबंधित सामान्य प्रश्न और उक्त संघ राज्यक्षेत्र के कार्यों के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों से संबंधित सेवा संबंधी मामले।

राम नाथ कोविन्द

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/15/2019-मंत्रि.]

रचना शाह, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2019

S.O. 3964(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Fifty Second Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(A) in THE FIRST SCHEDULE, under the heading "17. Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya)", for the sub-heading "(v) Department of Jammu and Kashmir Affairs (Jammu tatha Kashmir Vibhag)", the following sub-heading shall be substituted, namely:–

"(v) Department of Jammu, Kashmir and Ladakh Affairs (Jammu, Kashmir aur Ladakh Vibhag)";

(B) in THE SECOND SCHEDULE, under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)", for the sub-heading "E. DEPARTMENT OF JAMMU AND KASHMIR AFFAIRS (JAMMU TATHA KASHMIR VIBHAG)" and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be substituted, namely:–

"**E. DEPARTMENT OF JAMMU, KASHMIR AND LADAKH AFFAIRS (JAMMU, KASHMIR AUR LADAKH VIBHAG)**

A. General:

1. All matters falling within the purview of the Union Government in terms of provisions contained in Part VIII of the Constitution, in so far as these are applicable to the Union territory of Jammu and Kashmir or Union territory of Ladakh, as the case may be, except all such matters as have been specifically assigned under these rules to any other Ministry or Department of the Government of India.

2. All matters falling within the purview of the Union Government in terms of the provisions of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) relating to both the Union territories, except all such matters as have been specifically assigned under these rules to any other Ministry or Department of the Government of India.

3. All matters relating to the Union territory of Jammu and Kashmir or Union territory of Ladakh, as the case may be, including counter terrorism within the Union territory of Jammu and Kashmir and co-ordination with the Ministry of Defence as regards manning and managing the Line Of Control between India and Pakistan, but excluding those with which the Ministry of External Affairs is concerned.

4. Administration of the Armed Forces (Jammu and Kashmir) Special Powers Act, 1990 (21 of 1990) in both the Union territories.

5. Delegation of powers of State Government and Central Government under various enactments to the Administrator or the Lt. Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir or the Union territory of Ladakh, as the case may be, under article 239 of the Constitution.

B. Provisions specific to the Union territory of Ladakh:

6. Making of Regulations under article 240 of the Constitution for peace, progress and good government of the Union territory of Ladakh.

7. All matters enumerated in the State List and concurrent List in so far as any such matter concerns the said Union territory, except all such matters as have, under these rules, been specifically assigned to any other Ministry or Department of the Government of India.

8. General Questions relating to public services in the Union territory of Ladakh and service matters in so far as these fall within the purview of the State Governments.

C. Provisions specific to the Union territory of Jammu and Kashmir:

9. General Questions relating to public services in the said Union territory and service matters relating to the officers of the Indian Administrative Service and the Indian Police Service serving in connection with the affairs of the said Union territory.";

RAM NATH KOVIND

PRESIDENT

[F. No. 1/21/15/2019-Cab.]

RACHNA SHAH, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.10.31 23:27:40 +05'30'